राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निक्षेप

1061. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1990 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में किये गये कुल निक्षेपों में से 41.5 प्रतिशत निक्षेप देश के 13 शहरों में किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इन शहरों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी ऋण-राशि दी गई थी ;

(ग) इस अवधि के दौरान दी गई यह ऋण राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई कुल ऋण राशि का कितना प्रतिशत थी ;

(घ) क्या सरकार बैंकों द्वारा अति सीमित क्षेत्र में अधिकांश ऋण देने की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सितम्बर, 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 13 प्रमुख शहरों (बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कानपुर, चंडीगढ़, पटना और बड़ोदरा) में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां 75,392 करोड़ रुपए थी जो अखिल भारतीय बैंक जमाराशियों का 41.5 प्रतिशत बैठती है ।

(ख) सितम्बर, 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उक्त 13 शहरों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण 58,891 करोड़ रुपए के थे ।

(ग) उपरोक्त 13 शहरों में बकाया ऋण राशि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के कुल ऋण राशि का 50.1 प्रतिशत बैठता है ।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऋण वितरण में विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाए और कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादक और अर्थक्षम प्रस्तावों को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के कारगर कदम उठाये जाएं। बैंकों की अपनी-अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने के अनुदेश दिये गये हैं ।

देश में चल रहे विदेशी बैंकों में जमा राशि और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि का अनुपात

1062. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1990 के अंत तक देश में चल रहे विदेशी बैंकों में जमा राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की तुलना में अधिक थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई विशेष हिदायतें जारी की हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 28 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंको और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों

की जमाराशियां क्रमशः 111802 करोड़ रुपए और 10763 करोड़ रुपए थी। विदेशी बैंकों के परिचालनों की तुलना भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ करना उचित नहीं होगा क्योंकि विदेशी बकों के कार्यकरण का क्षेत्र कुछ महानगरीय केन्द्रो तक ही सीमित होता है इसके अलावा, विदेशी बैंकों के परिचालन का स्वरूप सीमित होता है जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क होता है और सेवा के लिए अनगिनत छोटे-छोटे ऋण खाते भी होते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन पर निरंतर आधार पर बारीकी से नजर रखता है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपाय भी किए जाते हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए स्वीकृत ऋण

1063. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कृषि क्षेत्र को कुल कितना ऋण प्रदान किया और यह इनके द्वारा दिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : सितम्बर 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों की बकाया राशि 16183.78 करोड़ रुपए थी जो 17.3 प्रतिशत बैठती है जबकि 1989 की तदनुरूप अवधि के लिए यह राशि 14986 करोड़ रुपए थी जो कुल अग्रिमो का 18.5 प्रतिशत बैठती है।

Reimbursement of Centrally Sponsored Projects

1064. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Centre has not reimbursed several Centrally sponsored projects carried out by the Uttar Pradesh Government during the financial year 1990-91;

(b) if so, what are the details of these projects; what is the amount promised and what is the amount paid by the Centre;

(c) whether the Utter Pradesh Government is insisting for immediate payment of all dues by the Centre; and

(d) if so, what is Central Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (d) The information is being collected and would be laid on the Table of the House as soon as it become available.

Setting up of Joint Ventures in Nepal

1065. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether some discussions for setting up of joint ventures in Nepal have been held:

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government propose to take some initiatives in this regard; and

(d) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHANTILAL PURUSHOTTAMDAS PATEL): (a) and (b) No specific discussions regarding setting up of Indo-Nepal joint ventures in Nepal have been held in the recent past.

(c) and (d) The establishment of joint ventures is an ongoing process between Indian and Nepalese firms.